रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216149 CG-DL-E-14022020-216149

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] No. 605] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941 23,1941 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12,2020/MAGHA 23,1941

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

सं. 09/2020

का.आ. 664(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा(1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को उनकी संबंधित क्षेत्र-अधिकारिता के भीतर उक्त धाराओं के प्रयोजन हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

[अधिसूचना सं.09/2020/ फा. सं. 285/41/2019-आईटी (अन्वे. V) सीबीडीटी] दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त(ओएसडी)(अन्वे.), सीबीडीटी

856 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

(Investigation Division-V)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2020

No. 09/2020

S.O. 664(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, hereby designates the Courts of the Chief Judicial Magistrates of the Union Territory of Jammu and Kashmir as Special Courts for the purposes of the said sections within their respective territorial jurisdictions.

[F. No. 285/41/2019-IT (Inv.V) CBDT]

DEEPAK TIWARI, Commissioner of Income Tax (OSD) (INV.), CBDT